केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 82 मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

एमएलसी चुनाव मतदान 23 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन–2026 हेतु मतदान आगामी 23 अक्टूबर को पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक सम्पन्न होगा। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने बताया कि जनपद में विद्यमान कुल 14 मतदेय स्थलों पर मतदान सम्पन्न कराया जायेंगा। इसको तहसील स्तर से लेखपालों के माध्यम से मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तैयार कराया जायेंगा।

उन्होने बताया कि जनपद में विद्यमान मतदेय स्थल 20 रामनगर, 21 रूधौली, 22 सल्टौआ गोपालपुर, 23 सॉऊघाट, 24 गौर, 25 परसरामपुर, 26 विक्रमजोत, 27 हर्रैया, 28 बस्ती, 29 नगरपालिका परिषद, बस्ती, 30 कप्तानगंज, 31 बहादुरपुर, 32 बनकटी तथा 33 कुदरहा के क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में अवस्थित तथा क्षेत्र पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र में निध ारित मतदान केन्द्र पर किया जायेंगा। इस निर्वाचन में केवल शिक्षक मतदाता होंगे।

बस्ती पहुंचा 250 पहियों वाला ट्रेलर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । 250 पहियों वाला 41 मीटर लंबा विशालकाय ट्रेलर सोमवार सुबह करीब 10 बजे बस्ती के पॉलिटेक्निक चौराहे पर पहुंचा तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस पर लदे भारी–भरकम साइक्लाइजेशन रिएक्टर को लखीमपुर खीरी स्थित बलरामपुर शुगर मिल तक पहुंचाया जाना है।

ट्रेलर के गुजरने के लिए बिजली के तार हटाने पड़े और एक सूखा पेड़ भी काटा गया। इस दौरान विद्युत विभाग, पुलिस, एनएच और यातायात विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भारी वाहन के कारण सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक एनएच पर यातायात प्रभावित रहा।

पंचायत सहायकों ने सौपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

कुदरहा, (बस्ती) । ग्राम सचिवालयों पर मूलभूत संसाधन व सुविधा मुहैया न होने से आजिज पंचायत सहायकों ने सोमवार को खंड विकास कार्यालय पर ब्लाक अध्यक्ष संदीप यादव के नेतृत्व मे दर्जनों की संख्या में पंचायत सहायकों ने खंड विकास अधिकारी व एडीओं पंचायत को नौ सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा। ब्लाक अध्यक्ष संदीप यादव ने बताया कि अधिकांश पंचायत भवनों पर विद्युत, इंटरनेट, पेयजल व शौचालय नही की व्यवस्था अभी तक नही है। पत्र दे कर अवगत कराया कि सचिवालय पर कंप्यूटर सिस्टम, वेब कैमरा, परिवार रजिस्टर तक नहीं है। जिससे गांव के लोगों को ब्लाक का चक्कर काटना पड़ रहा है। पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान व विभागीय परिचय पत्र जारी कराने की मांग किये। खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार पंकज ने बताया कि पंचायत सहायकों ने सचिवालय पर मूलभूत सुविधा व अन्य समस्याओं को लिखित पत्र दे कर अवगत कराए हैं। जांच कराकर सुविधा मुहैया कराया जाएगा।

विपक्ष का मार्च: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

नई दिल्ली (आभा)। राहुल, प्रियंका, खड़गे के साथ अन्य विपक्षी सांसद सोमवार शाम अचानक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे। पहले विपक्षी सांसदों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकाला था। एसआईआर में गड़बड़ी के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेता याचिकाकर्ता हैं। मार्च के पहले राहुल गांधी ने 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष का मार्च शिवजी की बारात की तरह है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है।

रविवार को विपक्षी सांसदों ने

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। लेकिन सीजेआई ने मिलने से इनकार कर दिया था और याचिका दाखिल करने के लिए कहा था।

इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि वह और विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के नेता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और ''संविधान बचाने की लड़ाई' जारी रखेंगे।

डीएम ने किया दुर्गा पूजा तैयारियों का निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दुर्गा पूजा त्योहार एवं मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने हर्रैया बाजार एवं महू घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहार के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन तथा मूर्ति विसर्जन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं सतर्कता के साथ करें।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा एवं मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी प्रदुम्न कुमार, क्षेत्राधि ाकारी पुलिस स्वर्णिमा सिंह, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी संजीव कुमार, अधिशासी अभियन्ता विद्युत शुभम पाण्डेय अधिशासी अधिकारी नगरपंचायत हर्रैया शिव प्रताप सिंह, हर्रैया के चेयरमैन कौशलेन्द्र प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

करंट लगने से युवक की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । परसरामपुर थाना क्षेत्र के नाथपुर पांडे गांव में सोमवार सुबह घर पर बिजली के बल्ब का तार ठीक करते समय करंट लगने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक की पहचान मुकेश कुमार चौहान पुत्र रामयज्ञ चौहान के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, मुकेश कुमार चौहान सोमवार सुबह करीब 8 बजे अपने घर पर विद्युत बल्ब का तार ठीक कर रहे थे। इसी दौरान वह अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से उनकी हालत बिगड़ गई। हादसे में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख–पुकार मच गई। युवक की अचानक मौत से परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है।बस्ती। परसरामपुर थाना क्षेत्र के नाथपुर पांडे गांव में सोमवार सुबह घर पर बिजली के बल्ब का तार ठीक करते समय करंट लगने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक की पहचान मुकेश कुमार चौहान पुत्र रामयज्ञ चौहान के रूप में हुई है।

आन्दोलन में हिस्सा लेने लखनऊ जा रहे डा. वी.के. वर्मा नजरबंद

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के मण्डल अध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा और डा. दिनेश सिंह कुशवाहा को नगर पुलिस ने सोमवार को उस समय गोटवा स्थित पटेल एस.एम. एच. हास्पिटल पर नजरबंद कर दिया जब वे मांगों के समर्थन में आन्दोलन में हिस्सा लेने लखनऊ जा रहे थे।

डा. वी.के. वर्मा ने बताया कि नियमितीकरण, समान कार्य–समान वेतन और सेवा सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर जनपद के 1100 संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने तीन दिनों तक कार्य बहिष्कार कर मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसके बावजूद जब मांगे नहीं मानी गई तो 12 अक्टूबर को लखनऊ में धरना दिया गया। डा. वर्मा ने कहा कि सरकार को दमन की जगह समस्याओं का समाधान करना चाहिये। कहा कि जब तक न्यायोचित मांगे पूरी नहीं हो जाती चरणबद्ध आन्दोलन प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुरूप जारी रहेगा।

हरीश द्विवेदी की माता को श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग

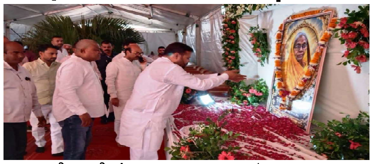

–संसार में मां का स्थान सर्वोच्च– इ. अरविन्द पाल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । नगर पंचायत बनकटी के अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रबल दावेदार इ. अरविन्द पाल ने नगर पंचायत के सभासदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के पैतृक गांव पहुंचकर उनकी माता जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अरविंद पाल ने दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मां की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई प्रेम नहीं है। मां का स्नेह और त्याग जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। मां का निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

इस दौरान इ. अरविन्द पाल के साथ नगर पंचायत बनकटी के सभासद विवेकानंद शुक्ला, बाबूराम चौधरी, बृजेश यादव, कौशल चौधरी, श्याम सुंदर चौधरी, ऋषि राज मुनि, विनोद यादव, दिनेश चौधरी, संजू चौधरी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद वसीम, वीरेंद्र अग्रहरि, साधु शरण, राजेंद्र यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त किया।

जन्तर-मन्तर पर अब नहीं होंगे प्रदर्शनः लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली (आभा)। दिल्ली के जंतर–मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसे निध ारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया है। सरकार ने 33 साल पहले जंतर–मंतर को प्रदर्शन की जगह तय किया था। गृह मंत्रालय की बनाई कमेटी की सिफारिश पर दिल्ली का रामलीला मैदान, बुराड़ी

ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का CBD ग्राउंड प्रदर्शन स्थल बनाए गए हैं। यहीं पर अन्ना आंदोलन, पहलवानों का प्रदर्शन, कॉकरोच पार्टी का ध ारना हुआ था।

कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे औरएस आईआर पर रोक की मांग को लेकर सोमवार को भी जंतर–मंतर पर प्रदर्शन की परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया।

2222 किसानों में 2 करोड़ 65 लाख 66 हजार रुपये की धनराशि वितरित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । प्रदेश सरकार के कृषि निवेश अनुदान/राहत सहायता वितरण कार्यक्रम के तहत सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार, में चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का सजीव प्रसारण के माध्यम से उनका उद्बोधन उपस्थित लोगों ने सुना। ।

जनपद में कुल 2222 किसानों के खाते में 2 करोड़ 65 लाख 66 हजार रुपये की धनराशि डिजिटल माध्यम से अंतरित की गई। सभागार में प्रतीकात्मक रूप से तहसील हर्रैया के 20 और तहसील सदर बस्ती के 10 किसानों को जिला पंचायत अध्यक्ष

संजय चौधरी, हर्रैया विधायक प्रतिनिधि सरोज मिश्रा, कप्तानगंज विधायक प्रतिनिधि गुलाब सोनकर, सदर विधायक प्रतिनिधि मो. सलीम अहमद, एमएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष सरवन तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से चेक वितरित किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि योगी सरकार में 'किसान समृद्ध तो उत्तर प्रदेश समृद्ध' का संकल्प साकार हो रहा है। अब किसानों को किसी बिचौलिए के पास जाने की जरूरत नहीं है, पैसा सीधे खाते में आ रहा है, यही पारदर्शी सरकार की पहचान है।

श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में 70 लाख रुपये की अत्याधुनिक एआई अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पूर्वांचल में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए पहचान बना चुके श्री कृष्णा मिशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। हॉस्पिटल में लगभग 70 लाख रुपये की लागत वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक पर आध ारित अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की गई है। अमेरिका से मंगाई गई इस आधुनिक मशीन से मरीजों की जांच सुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

पिछले करीब एक दशक से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत श्री कृष्णा मिशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार आधुनिक चिकित्सा संसाधनों को अपनाने पर जोर दे रहा है। इसी क्रम में एआई आधारित अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना को हॉस्पिटल की चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए हॉस्पिटल के डायरेक्टर पंकज चौध ारी ने बताया कि वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने और हॉस्पिटल को आधुनिक चिकित्सा तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से इस अत्याधुनिक मशीन को स्थापित कराया गया है।

उन्होंने बताया कि नई मशीन के माध्यम से अल्ट्रासाउंड जांच की गुणवत्ता और चिकित्सकों को जांच के दौरान मिलने वाली जानकारी में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इससे मरीजों को आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हॉस्पिटल को मजबूती मिलेगी।

पंकज चौधरी ने कहा कि श्री कृष्णा मिशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्देश्य मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी सोच के तहत समय–समय पर आधुनिक तकनीक और चिकित्सा संसाधनों को शामिल किया जा रहा है, ताकि मरीजों को बेहतर जांच और उपचार की सुविध ाएं मिल सकें।

हॉस्पिटल में अत्याधुनिक एआई अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना से बस्ती सहित पूर्वांचल के मरीजों को आधुनिक जांच सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह पहल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी रूप से और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस अवसर पर हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर वी के अय्यर, वरिष्ठ फिजिशियन डा.पी. पी. मिश्रा, वरिष्ठ सर्जन डा. नवीन मौर्या, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सोमा सा, एम डी रेडियोलॉजिस्ट डा.वीरेंद्र चौधरी, डा. अजीज आलम,दुर्गेश चौधरी, मनोज चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

डॉ. लोहिया ने आजाद भारत में सत्ता से सवाल पूछना सिखाया–महेन्द्रनाथ यादव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । समाजवादी आन्दोलन के अगुवा डॉ. राम मनोहर लोहिया को उनकी पुण्य तिथि पर याद किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉ. लोहिया के विचारों पर प्रकाश डालते हुये उन्हें नमन् किया।

समाजवादी पार्टी जिलाध यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि डा. लोहिया ने आजाद भारत में सत्ता से सवाल पूछना सिखाया और सत्ता के खिलाफ रहकर भारतीय राजनीति के साथ भारतीयों के मन–कर्म पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वह हमेशा समाज और सरकार को एक साथ, एक रास्ते पर और एक समान बनाने के लिए कार्य करते रहे। उनका समाजवाद विश्व इतिहास से सीखते हुए भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृ ति और भारतीय मानवतावाद से प्रभावित था।

पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, विधायक कविन्द्र चौधरी

–डॉ. राम मनोहर लोहिया को पुण्य तिथि पर समाजवादियों ने किया नमन्

'अतुल' दयाशंकर मिश्रा, समीर चौध ारी, मो. स्वाले, मो. सलीम, गुलाम गौस, अरविन्द यादव, प्रवीण पाठक, वृजेश मिश्र, रहमान सिद्दीकी, गीता भारती, विजय विक्रम यादव, संजय गौतम, अखिलेश यादव, अजय यादव आदि ने कहा कि लोहिया भारतीय राजनीति में समाजवाद के शिल्पी थे। डा. लोहिया चाहते थे कि दुनियाभर के सोशलिस्ट एकजुट होकर मजबूत मंच बनाए। उन्होने जनहित के सवालों को लेकर आजीवन संघर्ष किया।

वक्ताओं ने कहा कि राममनोहर लोहिया प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए, जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया उनमें से ही एक थे राममनोहर लोहिया। अपनी प्रखर देशभक्ति और समाजवादी विचारों के कारण डॉ. लोहिया ने अपने विरोधियों के बीच भी अपार सम्मान हासिल किया।

डा. राम मनोहर लोहिया के पुण्य तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम भवन यादव, संजय गौतम, हिमांशु सिंह 'रानू', विलाल अहमद, अकबर अली, जीत बहादुर सिंह, आर.डी. निषाद, जर्सी यादव, नित्यराम चौधरी, देवनाथ यादव, राजेन्द्र यादव, सन्जू प्रजापति, विजय लक्ष्मी, प्रिया श्रीवास्तव, राजेन्द्र चौरसिया, युनूस आलम, राम सिंह यादव, मधुबन यादव, दीपक आर्या, मो. हानिश, रहमान सिद्दीकी, प्रशान्त यादव, जोखूलाल यादव, निसार अहमद, प्रदीप यादव, विवेक यादव, अशोक यादव, रजवन्त यादव, तूफानी यादव, राम प्रकाश सुमन, घनश्याम यादव, मधुबन यादव, गुलाब सोनकर, अजय यादव, विक्की यादव, नवीन पाण्डेय, बदरूल हसन के साथ ही सपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

मारपीट में पति, पत्नी समेत तीन घायल, एसपी से लगाया मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाने की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के सिघौरवा गांव में मारपीट के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ओम प्रकाश पुत्र रामफेर ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें उनकी पत्नी समेत परिवार के कई लोग घायल हो गए। पीड़ित ने मामले में मुण्डेरवा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है।

पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में ओम प्रकाश ने कहा है कि आंखों में दिक्कत हैख वह अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनके घर के दो पहिया वाहन चलाने वाले चंद्रिका सिंह पुत्र केदारनाथ उनकी मदद करते हैं। आरोप है कि 7 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब सात बजे विवेक सिंह पुत्र चंद्रिका सिंह और राधिका सिंह उनके घर पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी ने कथित तौर पर गाली–गलौज का विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि विवेक सिंह ने कुल्हाड़ी से ओम प्रकाश की पत्नी सुनीता

देवी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनके नाक के ऊपर और दोनों आंखों के बीच गंभीर चोट आई। बीच–बचाव करने पहुंचे ओम प्रकाश पर भी राधिका सिंह ने लाठी से हमला कर दिया, जिससे उनके बाएं हाथ में चोट लग गई।

एसपी को दिये पत्र में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद शक्ति कपूर पुत्र राजदेव, राजदेव प्रसाद पुत्र रामफेर और दो अज्ञात व्यक्ति भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि सभी ने मिलकर चंद्रिका सिंह, ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। इस दौरान जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित के मुताबिक, घटना के बाद उन्होंने डायल 112 पर फोन किया। पुलिस घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंडेरवा ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पत्नी की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय बस्ती रेफर कर दिया गया। उनकी पत्नी सुनीता देवी अभी जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को घटना की सूचना मुंडेरवा थानाध्यक्ष को दी थी, लेकिन आरोप है कि अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की मांग की है।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 13 अक्टूबर 2026 मंगलवार

सम्पादकीय

जन्तर–मन्तर पर प्रतिबन्ध

दिल्ली पुलिस ने धरना–प्रदर्शन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नए आदेश के तहत जंतर–मंतर अब आधिकारिक प्रदर्शन स्थल नहीं रहेगा और इसे डीनोटिफाइड कर दिया गया है। रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए तय किया गया है। यह बदलाव गृह मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। गौर करने वाली बात है कि जंतर–मंतर से पहले दिल्ली में आधिकारिक धरना स्थल बोट क्लब था। बाद में बोट क्लब को हटाकर जंतर–मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल बनाया गया था। दिल्ली पुलिस का यह आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी किए गए पुराने स्टैंडिंग ऑर्डर में आंशिक बदलाव करता है। नई गाइडलाइंस के तहत राजधानी में धरना–प्रदर्शन के लिए तय स्थानों और उनसे जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। जंतर–मंतर लंबे समय से दिल्ली में विरोध–प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। नए आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों को निर्धारित नई जगहों पर प्रदर्शन करना होगा।

किसी समस्या के व्यापक असर और संदर्भ के मद्देनजर आम जनता को सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती है, तो यही अपने आप में सरकार की रीति–नीति पर एक सवालिया निशान है कि वह संवाद के सहारे समाधान का रास्ता तलाशने में नाकाम रही।

दूसरी ओर, सरकार के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने अपनी मांगों के साथ आंदोलन करने वाली जनता को ही प्रतिपक्ष मान लिया है और उसे रोकने के लिए हर संभव रास्ता अपना रही है। गौरतलब है कि काकरोच जनता पार्टी यानी काजपा के दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को घोषित प्रदर्शन की वजह से शांति भंग की आशंका जताते हुए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनसे यहां के आम जनजीवन के बाधित होने की स्थिति पैदा हो गई है।

विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के मकसद से शनिवार को दिल्ली में मेट्रो के सत्तावन स्टेशनों में प्रवेश और निकास द्वार को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने वाली कई गाड़ियों को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, राजधानी की सड़कों पर भी जगह–जगह अवरोधक लगाने और भारी संख्या में पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती की खबरें भी आईं।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बाद दिल्ली का जनजीवन किस स्तर तक प्रभावित होगा। यही वजह है कि इस मसले पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि सब कुछ बंद नहीं कर सकते और नागरिकों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

अव्वल तो किसी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को बाधित करने के बजाय लोगों को अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। अगर सरकार को ऐसा लगता भी है कि प्रदर्शन की वजह से कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है, तो बहुस्तरीय सख्ती की जगह उसे संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए और समाधान की गुंजाइश निकालनी चाहिए।

लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि उसमें जनता को सरकार की किसी कमी की शिकायत करने का अधिकार है और सत्ता इसका दमन नहीं करती है। विडंबना यह है कि काजपा के प्रदर्शन के आह्वान के बाद जिस तरह खासी संख्या में मेट्रो स्टेशनों को बंद करने, कई ट्रेनों को रद्द करने जैसे निर्देश जारी किए गए, उससे वास्तव में लोकतंत्र का जीवन ही बाधित होगा।

हैरानी की बात यह है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मसले पर उठे सवालों और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों के बावजूद अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं एसआइआर के खिलाफ शिकायतों का ठोस जवाब देने के बजाय सरकार प्रकारांतर से जनता के साथ आमने–सामने की मुद्रा में खड़ी दिख रही है। यह साफ है कि केवल पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में रखने के एसआइआर के घोषित उद्देश्य के बरक्स देश के अलग–अलग राज्यों में लाखों योग्य मतदाताओं को भी सूची से बाहर होना पड़ा।

इसके अलावा, फार्म–6 से लेकर नाम हटाने के लिए कई स्तर पर हुई गड़बड़ियों की जैसी शिकायतें सामने आई हैं, अगर उनका कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया, तो वे स्वतंत्र और स्वच्छ चुनाव को प्रभावित करेंगी। ऐसे में चुनाव आयोग से लेकर हर स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है, न कि लोकतांत्रिक विरोध के स्वर को दबाने की।

लोकतंत्र में असहमति अवांछित शोर नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता का प्रमाण है। ऐसे में जब देश के विभिन्न हिस्सों में युवा शिक्षा, रोजगार, अवसर और अधिकारों से जुड़े सवालों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो सबसे पहले उनके सवालों को सुनने की जरूरत है। पढ़ाई और करिअर बनाने की उम्र में एक समूची पीढ़ी अपनी ऊर्जा आंदोलन में लगाने को विवश हो, तो यह केवल उसकी बेचौनी नहीं, बल्कि व्यवस्था के लिए भी आत्ममंथन का विषय होना चाहिए।

विडंबना यह है कि आंदोलित युवाओं से संवाद करने और समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय सरकारी तंत्र सख्ती को ही रास्ता मान लेता है। कानून–व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हर असहमति को संदेह की नजर से देखना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं। विरोध और अराजकता एक नहीं हैं। सवाल उठाना व्यवस्था को चुनौती देना नहीं है। जब शासन नागरिकों के सवालों का उत्तर तर्क और संवाद के बजाय शक्ति से देने लगे, तो लोकतंत्र आदेश की भाषा में बदलने लगता है।

हालांकि लोकतंत्र की ताकत कठोरता में नहीं, आलोचना सुनने और अपनी नीतियों की समीक्षा करने की क्षमता में होती है। युवाओं के आंदोलनों को भीड़ और नारों के रूप में देखना आसान है, जबकि कठिन काम यह समझना है कि आखिर ऐसी कौन–सी परिस्थितियां हैं, जो भविष्य बनाने की उम्र में उन्हें सड़क पर आने को विवश करती हैं। उनके सवालों में अगर व्यवस्था की कमी दिखती है, तो उसे दबाने के बजाय खामी को दूर करना चाहिए।

अफसोस की बात यह है कि देश के अलग–अलग हिस्सों और खासतौर पर दिल्ली में युवाओं के आंदोलन के प्रति पुलिस का जैसा रवैया देखा जा रहा है, वह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। सत्ता की आलोचना, न्यायपूर्ण नीतियों की मांग और व्यवस्था में सुधार जैसे सवाल सुनने और समाधान की मांग करते हैं, न कि दमन के सहारे चुप कराए जाने की। सख्ती से कुछ समय के लिए सन्नाटा पैदा किया जा सकता है, लेकिन यह समाधान नहीं है। देशहित के सवालों पर सड़क पर उतरे युवाओं के साथ संवादहीनता की स्थिति से समस्या और भी जटिल हो सकती है। युवाओं के सवालों को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आन्दोलनों को कुचलने का सिलसिला कब बंद होगा।

पत्रकारों के अधिकारों पर पुलिसिया अतिक्रमण क्यों..?

—स्वदेश कुमार—

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका समाज को आईना दिखाने, सत्ता से तीखे सवाल करने और देशहित सर्वोपरि रखने की होती है। लेकिन वर्तमान समय में जनता के बीच यह गंभीर चिंता और विमर्श का विषय बन चुका है कि क्या आज का मीडिया अपनी इस मूल जिम्मेदारी को समझ पा रहा है। अक्सर यह देखा जाता है कि जिन नेताओं या शख्सियतों को जनता ने चुनावों में ठुकरा दिया है या जो जनभावनाओं पर खरे नहीं उतरे, उन्हें भी समाचार माध्यमों पर लगातार बड़ी सुर्खियां और विशेष कवरेज दी जाती है। इस विमर्श के केंद्र में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या मीडिया जानबूझकर देशहित की अनदेखी कर किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट कर रहा है या फिर इसके पीछे कुछ गहरे व्यावसायिक और राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं।इस पूरी स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें मीडिया के आधुनिक ढाँचे और उसके राजस्व मॉडल को देखना होगा। आज की पत्रकारिता केवल सूचना के आदान–प्रदान का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि वह एक बड़े उद्योग में तब्दील हो चुकी है। इस कॉर्पोरेट ढाँचे में टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग पॉइंट) और डिजिटल क्लिक्स ही सब कुछ तय करते हैं। जब कोई न्यूज चौनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी सनसनीखेज व्यक्तित्व, भले ही वह जनता द्वारा नकारा गया हो, को बार–बार स्क्रीन पर लाता है, तो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य दर्शकों का ध्यान खींचना होता है। विवाद, तीखे बयान और राजनीतिक ड्रामा दर्शकों को आकर्षित करते हैं, जिससे चौनलों की रेटिंग बढ़ती है और उन्हें विज्ञापन मिलते हैं। इस प्रक्रिया में देशहित के गंभीर मुद्दे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और बुनियादी विकास, पीछे छूट जाते हैं और मीडिया का झुकाव केवल उन चेहरों की तरफ हो जाता है, जो व्यावसायिक रूप से फायदेमंद होते हैं।

इसके अलावा, आज के मीडिया परिदृश्य में एजेंडा सेटिंग और मीडिया के मालिकाना हक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। कई बड़े मीडिया घरानों का स्वामित्व सीधे या परोक्ष रूप से उन कॉर्पोरेट समूहों या प्रभावशाली लोगों के हाथों में है, जिनके अपने विशिष्ट व्यावसायिक या राजनीतिक हित होते हैं। जब मीडिया का ढाँचा कुछ चुनिंदा हाथों में सिमट जाता है, तो निष्पक्षता की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी खास राजनेता या दल को बढ़ावा देना, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में और चाहे जनता ने उसे कितना भी नकारा हो, उस मीडिया घराने के दीर्घकालिक हितों का हिस्सा हो सकता है। यह स्थिति सीधे तौर पर देशहित से समझौता करती है, क्योंकि जनता को वह सच नहीं दिखाया जाता, जो उनके लिए जरूरी है, बल्कि वह नैरेटिव परोसा जाता है, जो किसी व्यक्ति या संगठन के अनुकूल हो।इस प्रवृत्ति को क्या देश के साथ बड़ी बेईमानी कहा जा सकता है, इसे विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखना होगा। जब मीडिया प्रशासन और जनता के बीच एक ईमानदार पुल का काम करने के बजाय किसी व्यक्ति विशेष की पीआर (पब्लिक रिलेशंस) एजेंसी की तरह व्यवहार करने लगता है, तो यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। जनता समाचारों को सत्य मानकर अपने लोकतांत्रिक निर्णय लेती है। यदि उसे बार–बार केवल एक ही पक्ष या किसी खास अप्रासंगिक चेहरे को ही सबसे बड़े मसीहा या मुख्य बिंदु के रूप में दिखाया जाएगा, तो जनमानस की सोचने–समझने की क्षमता प्रभावित होती है। यह देशहित के साथ इसलिए बेईमानी है, क्योंकि यह वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका कर देश के विकास की गति को धीमा करता है।

हालाँकि, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। लोकतंत्र में विपक्ष और असहमत आवाजों की मौजूदगी अनिवार्य है। कई बार मीडिया उन नेताओं को भी मंच देता है, जो चुनाव हार चुके होते हैं या जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा नापसंद किए जाते हैं, ताकि सत्ता पक्ष की नीतियों पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण सामने आ सके। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यह संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और जनसरोकार के मुद्दों को पूरी तरह दरकिनार करके केवल राजनीतिक नूराकुश्ती और व्यक्ति–केंद्रित बहसों को ही चौबीसों घंटे प्रसारित किया जाता है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से विमुख हो रहा है।लब्बोलुआब यह है कि ऐसी स्थिति केवल मीडिया की ही नहीं, बल्कि दर्शकों के रूप में समाज की भी परीक्षा लेती है। जब तक दर्शक सनसनीखेज खबरों और व्यक्ति–विशेष के प्रचार को देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक व्यावसायिक कारणों से मीडिया अपनी इस कार्यशैली को नहीं बदलेगा। आज की पत्रकारिता में विश्वसनीयता और तटस्थता की जो कमी दिख रही है, उसे दूर करने के लिए मीडिया घरानों को आत्ममंथन करने और देशहित को अपने व्यावसायिक लाभ से ऊपर रखने की सख्त आवश्यकता है, ताकि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ अपनी पवित्रता और जनता का विश्वास बनाए रख सके।

उच्च शिक्षा का दशक और गुणवत्ता

— संजीव कुमार मिश्र—

समावेशी विकास के हिमायती अर्थशास्त्री मानव पूंजी सिद्धांत के तहत शिक्षा को महज सामाजिक कल्याण या व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि उत्पादकता, नवाचार और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की बुनियादी पूंजी के रूप में देखते हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि किसी देश की युवा आबादी अपने आप में विकास की गारंटी नहीं होती। उसकी वास्तविक आर्थिक और सामाजिक क्षमता इस बात से निर्धारित होती है कि उसे उपलब्ध शिक्षा ज्ञान, कौशल और निर्णय क्षमता में कितना रूपांतरित कर पाती है। भारत आज इसी द्वंद्व के बीच खड़ा है। एक ओर विशाल युवा आबादी जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना प्रस्तुत करती है, दूसरी ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक श्रम बाजार में आते बदलाव मानव पूंजी निर्माण की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं।

ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस में 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी रेखांकित किया कि भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव का आर्थिक लाभ अनुकूल नीतिगत वातावरण, बेहतर स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार और लैंगिक सशक्तीकरण पर निर्भर करता है। इसलिए पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा के विस्तार और सुधारों का मूल्यांकन केवल संस्थानों तथा नामांकन की बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि इस कसौटी पर किया जाना चाहिए कि भारत अपनी युवा आबादी को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की सक्षम मानवीय शक्ति में कितना बदल पाया है।

इस दशक में भारतीय उच्च शिक्षा का सामाजिक आधार उल्लेखनीय रूप से विस्तृत हुआ है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार, कुल नामांकन 2014 से 15 के लगभग 3.42 करोड़ से बढ़कर 2023 से 24 में करीब 4.50 करोड़ हो गया। महिलाओं के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की भागीदारी भी बढ़ी है, जो उच्च शिक्षा के व्यापक सामाजिक विस्तार का संकेत है। हालांकि, नामांकन वृद्धि अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वास्तविक लोकतंत्रीकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पर्याप्त संसाधन और रोजगारपरक अवसरों तक समान पहुंच जरूरी है। महानगरों और छोटे शहरों के संस्थानों के बीच गुणवत्ता का अंतर अब प्रमुख चुनौती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्च शिक्षा सुधार के लिए व्यापक वैचारिक ढांचा प्रस्तुत किया। बहुविषयक अध्ययन, लचीली पाठ्यचर्या, शोध उन्मुख शिक्षा, कौशल विकास और अकादमिक क्रेडिट की हस्तांतरणीयता इसके प्रमुख प्रावधान हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विद्यार्थियों को शैक्षणिक यात्रा में अधिक लचीलापन देता है, जबकि समर्थ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश, परीक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की क्षमता रखते हैं। इन पहलों का महत्व संस्थागत विस्तार से आगे बढ़कर सीखने की गुणवत्ता, शैक्षणिक गतिशीलता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में है।

फिर भी नीतिगत महत्वाकांक्षा और संस्थागत वास्तविकता के बीच की दूरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुविषयक शिक्षा के लिए विभिन्न विषयों के सक्षम विभाग, प्रशिक्षित शिक्षक और पर्याप्त अकादमिक संसाधन चाहिए। शोध आधारित शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शोध अनुदान और मार्गदर्शन की व्यवस्था आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना सकते हैं, लेकिन वे कमजोर शिक्षण व्यवस्था की भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उसके प्रावधानों ने कक्षाओं में शिक्षण, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर और विश्वविद्यालयों की अकादमिक संस्कृति में कितना बदलाव पैदा किया है।

उच्च शिक्षा सुधार की केंद्रीय कसौटी शिक्षक व्यवस्था और शोध क्षमता है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा करने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि ज्ञान सृजन, आलोचनात्मक विवेक और बौद्धिक स्वतंत्रता के वाहक हैं। अनेक संस्थानों में रिक्त पदों, संविदा नियुक्तियों और गैर शैक्षणिक दायित्वों का दबाव शिक्षण, शोध निर्देशन और विद्यार्थियों से संवाद को प्रभावित करता है। इसलिए पारदर्शी नियुक्ति, अकादमिक स्वतंत्रता और निरंतर प्रशिक्षण को दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना आवश्यक है।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता शोध और नवाचार में उनके योगदान से भी निर्धारित होती है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन व्यापक विश्वविद्यालय व्यवस्था में शोध संस्कृति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कृषि, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध अवसर प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए शोध वित्तपोषण बढ़ाने, उद्योग और अकादमिक संस्थानों के सहयोग तथा युवा शोधकर्ताओं को स्वतंत्र अवसर देने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों को ज्ञान के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके उत्पादक केंद्र बनाना होगा। इसी तरह रोजगार और उच्च शिक्षा के संबंध को भी अधिक सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। डिग्री और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता, व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योग की बदलती मांगों पर प्रश्न उठाती है। तकनीकी दक्षता, डिजिटल साक्षरता, संचार क्षमता और समस्या समाधान जैसे कौशल अब अनेक क्षेत्रों में आवश्यक हो गए हैं। फिर भी, रोजगारोन्मुखी शिक्षा का अर्थ विश्वविद्यालयों को उद्योग की तात्कालिक जरूरतों के अधीन कर देना नहीं है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषय विद्यार्थियों में ऐतिहासिक चेतना, नैतिक विवेक, लोकतांत्रिक समझ और समाज के जटिल प्रश्नों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करते हैं। एक सक्षम उच्च शिक्षा व्यवस्था को आर्थिक उपयोगिता और बौद्धिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कायम करना होगा। उसका उद्देश्य केवल रोजगार पाने योग्य व्यक्ति तैयार करना नहीं, बल्कि ज्ञानवान, विवेकशील और उत्तरदायी नागरिक बनाना भी है।

हाल में बिहार में 211 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों की शुरुआत, 2,451 संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति तथा विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और डिजिटल सुधारों की पहल इसी राष्ट्रीय चुनौती का एक प्रासंगिक उदाहरण है। इन प्रयासों से उच्च शिक्षा की भौगोलिक पहुंच और संस्थागत क्षमता बढ़ाने की संभावना बनती है। लेकिन इनकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कॉलेजों में नियमित शिक्षण, पर्याप्त संसाधन, अकादमिक नेतृत्व और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का वातावरण कितना विकसित होता है। बिहार का अनुभव इस व्यापक तथ्य को रेखांकित करता है कि संस्थानों की संख्या बढ़ाना सुधार का प्रारंभिक चरण है, उसकी परिणति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ही हो सकती है।

ये पूरा दशक भारतीय उच्च शिक्षा में विस्तार और संस्थागत परिवर्तन का दौर रहा है, लेकिन अगली चुनौती कहीं अधिक जटिल है। बढ़ता नामांकन, महिलाओं और वंचित समूहों की भागीदारी तथा डिजिटल प्रशासन सकारात्मक आधार तैयार करते हैं, पर गुणवत्ता, शिक्षक उपलब्धता, शोध क्षमता और रोजगारपरकता की चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। इसलिए उच्च शिक्षा नीति का केंद्र अब मात्र विस्तार नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और समान अवसरों का निर्माण होना चाहिए। भारत की युवा आबादी तभी वास्तविक जनसांख्यिकीय लाभांश में बदल सकती है, जब शिक्षा उसे ज्ञान, कौशल और नवाचार की क्षमता प्रदान करे। आने वाले दशक की अग्निपरीक्षा इसी रूपांतरण में निहित है।—

प्रतिभा की परीक्षा या संसाधनों की ताकत?

— डॉ. सत्यवान सौरभ—

भारतीय समाज में आईएएस और एचसीएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं में चयन को प्रतिभा, परिश्रम, अनुशासन और मेधा की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। इन सेवाओं में पहुँचने का सपना लाखों युवा देखते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही अभ्यर्थियों को मिल पाती है। इस लंबी प्रतिस्पर्धा के बीच एक सवाल बार–बार उठता है कि क्या इन परीक्षाओं में केवल प्रतिभा और मेहनत निर्णायक होती हैं, या अभ्यर्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संसाधन भी उसकी सफलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाए, तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में मौजूद अवसरों की असमानता के कई पहलू सामने आते हैं। जब किसी एचसीएस या आईएएस टॉपर की सफलता की कहानी सामने आती है, तो उसके अंकों, रैंक, मेहनत और संघर्ष की चर्चा होती है। कई बार यह जानकारी भी सामने आती है कि अभ्यर्थी कई वर्षों से तैयारी कर रहा था या अनेक बार संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा तक पहुँचा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी छह बार आईएएस की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के बाद भी प्रयास जारी रखता है और अंततः राज्य की प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त करता है, तो उसकी मेहनत निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी उठता हैकृक्या प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को इतने लंबे समय तक तैयारी जारी रखने का अवसर मिल पाता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल व्यक्तिगत इच्छाशक्ति में तलाशना उचित नहीं होगा। तैयारी के लिए समय चाहिए, आर्थिक सुरक्षा चाहिए और असफलताओं के बाद दोबारा खड़े होने का अवसर भी चाहिए। किसी अभ्यर्थी के परिवार के पास पर्याप्त संपत्ति हो, माता–पिता अच्छी नौकरी में हों या परिवार की नियमित आय इतनी हो कि कई वर्षों तक पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके, तो उस अभ्यर्थी को तैयारी के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। इसके विपरीत, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए भी घर की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाता। उसे किताबों, कोचिंग और परीक्षा के खर्च की व्यवस्था करने के साथ–साथ परिवार की आजीविका के बारे में भी सोचना पड़ता है।

मान लीजिए, दो युवा समान प्रतिभाशाली हैं। दोनों की शैक्षणिक क्षमता भी लगभग समान है। पहले युवा के परिवार के पास पर्याप्त संपत्ति है। उसके रहने, खाने, पढ़ने और परीक्षा देने का खर्च परिवार उठा सकता है। वह लगातार पाँच या छह वर्षों तक अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। दूसरी ओर, दूसरे युवा के पिता किसान, मजदूर या छोटे कर्मचारी हैं। परिवार की आय सीमित है और घर में उसके अलावा भी कई लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे नौकरी करने या परिवार की आर्थिक सहायता के लिए दूसरा रास्ता तलाशना पड़ता है। दोनों के बीच अंतर केवल प्रतिभा का नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों का भी है जिनमें उनकी प्रतिभा विकसित होती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए केवल पाठ्यक्रम पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता। नियमित अध्ययन, समसामयिक घटनाओं की जानकारी, उत्तर लेखन का अभ्यास, वैकल्पिक विषय की तैयारी, साक्षात्कार की समझ और लगातार अपनी कमियों को सुधारने की आवश्यकता होती है। कई अभ्यर्थी महँगी कोचिंग, अच्छे पुस्तकालय, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन और जानकार लोगों के संपर्क से लाभ उठाते हैं। दूसरी ओर, अनेक युवा इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री, पुरानी पुस्तकों और सीमित संसाधनों के सहारे तैयारी करते हैं। डिजिटल माध्यमों ने अध्ययन सामग्री तक पहुँच आसान जरूर की है, लेकिन शांत वातावरण, उचित मार्गदर्शन और आर्थिक सुरक्षा का महत्त्व समाप्त नहीं हुआ है।

यहाँ एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संपन्न परिवार से आने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी सुविधाओं के कारण ही सफल होता है, ऐसा कहना गलत होगा। प्रशासनिक सेवाओं में चयनित अनेक युवा कठिन परिस्थितियों से निकलकर भी सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ, आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के अनेक अभ्यर्थी भी असफल होते हैं। सफलता के लिए परिश्रम, बौद्धिक क्षमता, निरंतरता, परीक्षा की समझ और मानसिक दृढ़ता आवश्यक हैं। इसलिए बहस का उद्देश्य किसी सफल अभ्यर्थी की उपलब्धि को कमतर आँकना नहीं, बल्कि यह समझना होना चाहिए कि अलग–अलग सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में रहने वाले युवाओं को तैयारी के कितने समान अवसर मिलते हैं।

इसी प्रकार, किसी अभ्यर्थी के माता–पिता का उच्च पद पर कार्यरत होना या परिवार का राजनीति में सक्रिय होना अपने आप में अनुचित लाभ का प्रमाण नहीं है। ऐसे परिवारों में प्रशासनिक व्यवस्था की समझ, बेहतर शैक्षणिक मार्गदर्शन और प्रेरणा का वातावरण उपलब्ध हो सकता है। लेकिन केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी की योग्यता पर संदेह करना भी उचित नहीं है। आवश्यक यह है कि इस विषय पर धारणाओं के बजाय प्रमाणों के आधार पर चर्चा की जाए।

यदि यह जानना है कि आईएएस और एचसीएस में सफल होने वाले अभ्यर्थियों में संपन्न परिवारों से आने वालों का अनुपात कितना है, तो इसके लिए व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारिवारिक आय, माता–पिता के व्यवसाय, ग्रामीण या शहरी पृष्ठभूमि, शिक्षा पर हुए खर्च, तैयारी में लगे वर्षों और उपलब्ध मार्गदर्शन जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए। बिना विश्वसनीय आँकड़ों के यह दावा करना कि 99.99 प्रतिशत सफल अभ्यर्थी संपन्न परिवारों से आते हैं, तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। लेकिन इस दावे के पीछे छिपे अवसरों की असमानता संबंधी प्रश्न को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार और संबंधित संस्थाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को अधिक समावेशी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क मार्गदर्शन, जिला स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय, डिजिटल अध्ययन केंद्र, उत्तर लेखन का अभ्यास, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी आर्थिक सहायता उपयोगी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को भी वही शैक्षणिक संसाधन और जानकारी मिलनी चाहिए, जो बड़े शहरों में तैयारी करने वालों को उपलब्ध होती है। साथ ही, सहायता योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुँचे, इसके लिए नियमित समीक्षा भी जरूरी है।

प्रशासनिक सेवाओं में चयनित अधिकारी भविष्य में समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह भी आवश्यक है कि इन सेवाओं तक पहुँचने के रास्ते सामाजिक विविधता और समान अवसरों को प्रोत्साहित करें। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी तैयारी के अवसरों को व्यापक बनाना भी है।

अंततः सवाल यह नहीं है कि संपन्न परिवारों के बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में क्यों सफल होते हैं। सवाल यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए किन बाधाओं से गुजरना पड़ता है। किसी युवा को छह बार मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलना उसकी निरंतरता और मेहनत का परिचायक हो सकता है, लेकिन हर युवा को ऐसा अवसर उपलब्ध नहीं होता।

विपक्ष के रहमोकरम पर अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेः बृजभूषण बोले– राहुल गांधी कई दिनों से राग अलाप रहे, विदेशी फंडिंग से देश को अस्थिर करने की साजिश

संवाददाता–गोण्डा। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर पूरे विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा– विपक्ष जनता की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहा, बल्कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बना रहा है। जब आप चुनाव जीत जाते हैं, तब चुनाव आयोग अच्छा होता है, लेकिन जब हार जाते हैं तो वही आयोग खराब हो जाता है। अमित शाह देश के गृहमंत्री हैं। वह चुनाव लड़कर और जीतकर आए हैं। देश में जब कैबिनेट बनी तो उन्हें गृहमंत्री बनाया गया। वह आपके रहमोकरम पर नहीं बने हैं। ये आंदोलन विदेशी फंडिंग के सहारे किया जा रहा है। इससे देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है।

ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाले बताएं कि केपीएस गिल की नियुक्ति किस कानून के तहत हुई थी और नवीन चावला की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी। देश में पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि प्रदर्शन किस मुद्दे पर है। बृजभूषण शरण सोमवार सुबह 11 बजे अपने पैतृक आवास विश्नोहरपुर में जनता दर्शन में बोल रहे थे। उन्होंने कई जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन के बाद उन्होंने श्रंच के प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों की मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात नहीं होने और राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर बयान दिया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक नामित सदस्य के रूप में गृहमंत्री शामिल हैं। वर्ष 2023 से पहले देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संसद ने नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई और उसी के तहत ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई।

यदि ज्ञानेश कुमार विपक्ष को पसंद नहीं हैं, तो इसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि विपक्ष के पास कोई सबूत या साक्ष्य है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। कहीं कानून का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम रास्ता है। राहुल गांधी के प्रदर्शन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा – राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मौजूदा आंदोलन के समय पर सवाल उठते हैं। राहुल जी, यह राग आप बहुत दिन से अलाप रहे हैं, लेकिन टाइमिंग देखिए। एक उद्योगपति का बयान आता है और वह उसे ट्वीट करता है। राहुल जी उसे रीट्वीट करते हैं। यहीं संदेह पैदा हो जाता है कि आंदोलन किया नहीं जा रहा, बल्कि कराया जा रहा है।"

दो दिन पहले कॉकरोच नाम के जीव भी इस बार नहीं आ पाए। उन्होंने इस संदर्भ में भी आंदोलन कराए जाने की आशंका जताई। बृजभूषण ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी, पढ़ने वाले बच्चे, नौकरीपेशा लोग और आने–जाने वाले लोग परेशान हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि दिल्ली से 10 से 20 किलोमीटर दूर कोई मैदान निर्धारित कर दिया जाए, जहां लोग धरना–प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि जंतर–मंतर पर किसी को भी धरना–प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विपक्षी सांसदों की सीजेआई से मुलाकात नहीं होने के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह देश में एक अलग तरह की घटना है कि आंदोलनकारी मुख्य न्यायाधीश से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति से भी मिलना चाहते थे और राष्ट्रपति ने उनसे मुलाकात कर उनकी बात सुनी। अब प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से भी मिलना चाहते हैं और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष निष्पक्ष न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। सीजेपी के अभिजीत दीपक के बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा– मैं दिल्ली पुलिस और अभिजीत दीपके के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। विदेशी फंडिंग के सहारे देश को अस्थिर करने की तैयारी की जा रही है और इसी वजह से आंदोलन कराया जा रहा है। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से वोट चोरी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि जिसके पास सबूत हैं, वह उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। राहुल गांधी के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान सबूत नहीं ले जाने पर कहा– प्रधानमंत्री को तो आप प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं होता। अब जो सबूत आपके पास हैं, वे राष्ट्रपति को दीजिए। जब मिलने गए थे, तो सबूत लेकर क्यों नहीं गए? इनके पास कुछ है नहीं।" चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा– विपक्ष हारने पर अपनी हार छिपाने और जनता को भ्रमित करने के लिए सारा दोष चुनाव आयोग पर डाल देता है। बिहार, बंगाल और पुराने चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। राहुल गांधी के उस बयान पर कि चुनाव आयोग के कार्यालय का नाम बदलकर भाजपा कार्यालय कर देना चाहिए, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने नवीन चावला और केपीएस गिल के कार्यकाल में भी चुनाव होते देखे हैं। यदि किसी मतदाता का नाम तीन जगह दर्ज है और अब उसे एक जगह कर दिया गया है, तो इसमें क्या परेशानी है? यदि किसी का नाम मतदाता सूची से कट गया है, तो उसे न्यायालय जाना चाहिए।

कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन

संवाददाता–गोण्डा। कांग्रेस सांसद और जेएनयू के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को लेकर सोमवार शाम भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष बीना राय के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंचीं और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर कांग्रेस के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने 'महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' और 'महिला विरोधी कांग्रेस' जैसे नारे लगाए। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आरोपों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।

भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बीना राय ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर नारी शक्ति एकजुट होकर आवाज उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीना राय ने कहा कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता पर आरोप लगने पर कांग्रेस के नेता मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अपने सांसद पर लगे आरोपों पर पार्टी की ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।

भारतीय किसान यूनियन ने जताई गड़बड़ी की आशंका

संवाददाता–श्रावस्ती। भारतीय किसान यूनियन के मध्यांचल महासचिव विनोद कुमार शुक्ल ने आरोप लगाया कि इतने कम समय में सभी प्रभावित किसानों की फसलों का वास्तविक स्थलीय सर्वे करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। उनका कहना है कि एक राजस्व गांव में खेतों का मौके पर जाकर सही ढंग से सर्वे करने में कम से कम दो दिन लग सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल के मुताबिक, जल्दबाजी में सर्वे का लाभ उठाकर कुछ लेखपाल अपने कमरों पर बैठकर किसानों से खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करवा रहे हैं। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है। साथ ही समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाने वाले कई प्रभावित किसान सरकारी सहायता से वंचित रह सकते हैं। किसान नेता ने आशंका जताई कि यदि सर्वे प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं अपनाई गई तो वास्तविक नुकसान झेलने वाले किसानों के नाम छूट सकते हैं। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि चयन प्रक्रिया में पक्षपात होने पर कुछ किसानों को अनुचित लाभ मिल सकता है और सरकारी धन के वितरण में अनियमितता की संभावना बढ़ सकती है।

सेवानिवृत्ति पर शारीरिक शिक्षक छोटेलाल यादव को दिया भावभीनी विदाई

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित 17वीं जनपद स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान सोमवार को जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, ओड़वारा के सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक छोटेलाल यादव का भव्य सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। बीते मार्च में सेवानिवृत्त हुए छोटेलाल यादव को जनपद के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों ने माल्यार्पण कर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षकों ने उनके सेवाकाल और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया।

समारोह में शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक का दायित्व केवल विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और खेल भावना का विकास होता है। ऐसे में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का योगदान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में विशेष महत्व रखता है। छोटेलाल यादव ने अपने सेवाकाल में शैक्षिक गतिविधियों के साथ शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथी शिक्षकों की ओर से आयोजित इस सम्मान समारोह में आत्मीयता और सम्मान का भाव देखने को मिला। शिक्षकों ने उनके साथ बिताए गए समय को याद करते हुए उनके स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना की। समारोह के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने सहकर्मियों के बीच उनके प्रति सम्मान और अपनत्व का भाव प्रदर्शित हुआ। कार्यक्रम का संचालन अजय कुमार वर्मा ने किया। समारोह में प्रधानाचार्य हरिराम बंसल, प्रमोद कुमार उपाध्याय, अमित यादव, माता प्रसाद त्रिपाठी, संतोष कुमार पांडेय, विवेक श्रीवास्तव, रमेश चंद्र गुप्ता, हरीश सिंह, वेद प्रकाश द्विवेदी, सुरेंद्र कुमार शुक्ला, प्रभाकर सिंह, विनय सिंह, राजकुमार यादव, शैलेंद्र कुमार, अरुण और कृष्ण कुमार पाठक सहित जनपद के अनेक शारीरिक शिक्षा शिक्षक उपस्थित रहे।

हरीश द्विवेदी की माता के निधन पर वीसी पाण्डेय ने दूरभाष के जरिए व्यक्त की शोक संवेदना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की माता के निधन पर बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र 308 से भाजपा के भावी उम्मीदवार वृन्दावन चन्द्रभान पाण्डेय उर्फ वीसी पाण्डेय ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए शोक संवेदना प्रकट की तबीयत खराब होने के कारण वरिष्ठ भाजपा नेता वृन्दावन चन्द्रभान पाण्डेय उर्फ वीसी पाण्डेय शोकाकुल परिवार से मिलने उनके पैतृक आवास ग्राम तेलियाजोत नहीं पहुंच सके उन्होंने दूरभाष के माध्यम से हरीश द्विवेदी और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं तथा इस दुःख की घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया भाजपा के वरिष्ठ नेता वृन्दावन चन्द्रभान पाण्डेय उर्फ वीसी पाण्डेय ने कहा कि मां का साया सिर से उठ जाना जीवन की सबसे बड़ी पीड़ाओं में से एक है माता का निधन परिवार के लिए ऐसी अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती इस कठिन समय में वह शोक संतप्त परिवार के दुःख में वह सहभागी हैं उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी सहित समस्त शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करें।

250 किसानों को मिला मुआवजा, 250 से अधिक को मिनीकिट बीज वितरित

संवाददाता–गोण्डा। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सोमवार दोपहर करीब तीन बजे जिला पंचायत सभागार में कृषि निवेश अनुदान एवं आपदा राहत सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें चक्रवात से प्रभावित 250 किसानों को करीब पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से 250 से अधिक किसानों को चना, मसूर, मटर और सरसों समेत विभिन्न फसलों के मिनीकिट बीज वितरित किए गए। इससे किसानों को अगली फसल की बुवाई में मदद मिलेगी। चक्रवात के कारण जिले में कई किसानों की धान और गन्ने समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा था। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। कृषि विभाग ने फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट आपदा विभाग को भेजी थी। इसके बाद प्रभावित किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराई गई।

किसानों को राहत देने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बीज मिनीकिट भी वितरित किए गए। इनमें चना, मसूर, मटर और सरसों के बीज शामिल हैं। विभाग का उद्देश्य किसानों को आगामी सीजन में बुवाई के लिए प्रोत्साहित करना और खेती के काम को सुचारु रूप से जारी रखने में मदद करना है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को कृषि और आपदा राहत से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि जिन किसानों की फसल या अन्य संपत्ति को नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि जिन किसानों की फसल या अन्य संपत्ति को नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि जिन किसानों की फसल या अन्य संपत्ति को नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को बीज भी वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

कार्यक्रम में विधायक मेहनौन विनय कुमार द्विवेदी, विधायक गोंडा प्रतीक भूषण सिंह, डीएम प्रियंका निरंजन और अपर जिलाधिकारी प्रमोद झा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पात्र किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

189 जोड़ों ने थामा एक–दूजे का हाथ

संवाददाता–देवरिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सोमवार को लार रोड स्थित राजकुमारी हृदय नारायण सिंह पैलेस में 189 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चले कार्यक्रम में 177 हिंदू जोड़ों ने सात फेरे लिए, जबकि 12 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने नवदंपतियों को सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया।

समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, राज्यमंत्री के प्रतिनिधि राम मनोहर यादव, सलेमपुर सांसद के प्रतिनिधि रामप्रकाश यादव, लार ब्लॉक प्रमुख अमित कुमार सिंह और सलेमपुर ब्लॉक प्रमुख अमरेश कुमार सिंह मौजूद रहे।

इसके अलावा उप जिलाधिकारी न्यायिक सलेमपुर राम नारायण सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, तहसीलदार सलेमपुर सुशील कुमार और खंड विकास अधिकारी भाटपाररानी एवं सलेमपुर पीएन त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को सुखी और सफल दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर कुल एक लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। इसमें 64 हजार रुपये विवाहित कन्या के बैंक खाते में दिए जाते हैं। वहीं, 21 हजार रुपये की उपहार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और विवाह का खर्च उठाने में परिवारों को राहत देना है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत अगला सामूहिक विवाह कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2026 को देवरिया स्थित राजकीय आईटीआई में प्रस्तावित है। इसके माध्यम से पात्र जोड़ों को विवाह के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

संवाद और जागरूकता से मानसिक रोगों से होगा बचाव

संवाददाता–देवरिया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शहर के कसया रोड स्थित एक होटल में रोटरी क्लब देवरिया द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता ने कहा कि संवाद व जागरूकता से मानसिक रोगों का बचाव होगा। आधुनिक जीवन शैली मानसिक बीमारी को बढ़ावा दे रही है। मानसिक रोग के सम्बन्ध में समाज में व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करना होगा। मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप श्रीवास्तव ने बच्चों, जवानों से लेकर बुजुर्गों में होने वाले मानसिक रोग के लक्षणों की जानकारी दी। कहा कि हर 7 में से एक व्यक्ति है मानसिक रोग का शिकार है तथा 13 फीसदी लोगों को मानसिक रोग होने की संभावना रहती है। 70 से 90 फीसदी मानसिक रोगी हेल्प नहीं लेते हैं। समय से पहचान कर मानसिक रोगों का इलाज हो सकता है। विशिष्ट अतिथि डा. विवेक मिश्र ने कहा कि मानसिक रोगियों को पहचानना,समुचित सहायता देना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों में संवाद और आत्मीयता की कमी, प्रगति की अंधी दौड़ से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आईटीआई प्रधानाचार्य केके राम ने कहा कि अतिरिक्त कार्य का बोझ, खराब जीवन शैली को मानसिक रोग का प्रमुख कारक है। क्लब के अध्यक्ष रोट राकेश धर द्विवेदी ने कहा कि क्लब समय समय पर सामाजिक मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है। संचालन हिमांशु कुमार सिंह व आभार सिद्ध नाथ चतुर्वेदी ने जताया। इसमें इमरान लारी, गोपाल कृष्ण सिंह रामू, प्रभाकर मिश्र, अमित त्रिपाठी, विनोद यादव, मिथिलेश कुशवाहा, विजय सिंह, डा. अविनाश चौरसिया, संदीप गुप्ता, संदीप मल्ल, अविनाश सिंह, सुजीत मिश्रा, अविनाश बैरनवाल, पुष्प प्रकाश तिवारी, रणजीत सिंह, अनिल गुप्ता, अजय जायसवाल, सत्येन्द्र शुक्ला, राकेश सिंह, विपिन यादव, विजय चौरसिया, तेज पुंज त्रिपाठी, डा. अभिनव सिंह आदि मौजूद रहे।

मिशन शक्ति की रैली में गूंजा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन का संदेश

संवाददाता–महराजगंज। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को नगर में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हुई। नगर के उद्योग केंद्र चौराहे से डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली के दौरान पूरे मार्ग पर महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता व सम्मान का संदेश गूंजता रहा। रैली को रवाना करने के दौरान डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री व एवं शासन के निर्देश पर शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों के लिए यह विशेष अभियान शुरु किया गया है। जिले में महिला पुलिस कर्मियों, प्रोबेशन विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को एकजुट कर अभियान का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि नौ दिनों तक अलग–अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। पिंक बूथ, महिला थाना, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत सहायकों के माध्यम से गांव–गांव और शहर–शहर संदेश पहुंचाया जाएगा। डीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन की नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की है। जागरूकता रैली में महिला पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य विभागों की महिला कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर एएसपी सिद्धार्थ, सीओ सदर अंकुर गौतम, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इन्द्र कुमार सिंह सहित कई अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

गाजे–बाजे के साथ शतचंडी महायज्ञ की कलश यात्रा निकाली

संवाददाता–महराजगंज। घुघली क्षेत्र के जखीरा बाजार शिव मंदिर प्रांगण से शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हो गया। यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण पाठक, योगेश्वर पांडेय, अम्बरीश पांडेय, गंगेश्वर पांडेय व मुख्य यजमान सुदर्शन सिंह, रामानन्द की अगुआई में गाजे–बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई कलश यात्रा चौमुखा, मेदिनीपुर, पकड़ियार विशुनपुर, हरखा प्यास, हरखा आदि गांवों का भ्रमण करते हुए छोटी गंडक नदी वालाछत्र घाट पर पहुंचीं, जहां महिलाओं व बालिकाओं ने कलश में जल भरा। फिर यात्रा यज्ञस्थल पर पहुंची, जहां मंदिर के पुजारी अमरनाथ की देखरेख में कलश स्थापित कराए गए। कलश यात्रा में सुनील कुमार उपाध्याय एडवोकेट, राम ध्यान मल्ल, सौरभ उपाध्याय, पूर्व प्रधान रामनजन प्रजापति, धनंजय चौहान, राजेश शर्मा, रोहित गौड़, ओंकार चौधरी, जितेंद्र चौधरी, ज्ञान चंद गुप्ता, रविन्द्र गौड़ सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे।

लेहड़ा देवी मंदिर पहुंचे डीएम, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

संवाददाता–महराजगंज। शारदीय नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। देवी मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शन–पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने फरेंदा स्थित प्रसिद्ध लेहड़ा देवी मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा–अर्चना की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने आयोजकों को भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम के मुताबिक, नवरात्रि के दौरान भारत के साथ नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लेहड़ा देवी मंदिर में दर्शन–पूजन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ प्रबंधन, कानून–व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि नवरात्रि का पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए। महराजगंज के फरेंदा स्थित प्रसिद्ध लेहड़ा देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने मंदिर पहुंचकर पूजा–अर्चना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को दर्शन–पूजन में किसी तरह की असुविधा न हो। खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और कानून–व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। प्रशासन का दावा है कि नवरात्रि के दौरान जिले के सभी प्रमुख मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों पर सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

देवीपाटन मंडल में 1 लाख से ज्यादा स्टडी टेबल वितरित, 77 छात्रों ने सीएम को भेजा आभार पत्र, जवाब में मिला आशीर्वाद

संवाददाता–गोण्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संचालित 'देवीपाटन शिक्षा की उड़ान' अभियान के तहत देवीपाटन मंडल के चार जिलों में 1,06,805 मेधावी छात्र–छात्राओं को स्टडी टेबल वितरित की जा चुकी हैं। सोमवार दोपहर तीन बजे कमिश्नर कार्यालय में स्टडी टेबल और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों बच्चों को स्टडी टेबल वितरित की गईं।

स्टडी टेबल मिलने के बाद 77 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को हस्तलिखित आभार पत्र भेजे थे। इन पत्रों के जवाब में मुख्यमंत्री ने बच्चों को आत्मीय संदेश और आशीर्वाद पत्र भेजकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री के इस संदेश से विद्यार्थियों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला।

मुख्यमंत्री के आशीर्वाद पत्र वितरण की शुरुआत रविवार को बलरामपुर में छात्रों को पत्र सौंपकर की गई थी। सोमवार को गोंडा में मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री का संदेश सौंपा। वहीं, श्रावस्ती में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी तथा बहराइच में जिलाधिकारी ने बच्चों को आशीर्वाद पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री को आभार पत्र भेजने वाले 77 विद्यार्थियों में गोंडा के 26, श्रावस्ती के 18, बहराइच के 17 और बलरामपुर के 16 बच्चे शामिल हैं। इनमें गोंडा के सबसे ज्यादा 26 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री की ओर से जवाब मिला। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, गोंडा में 32,638, बहराइच में 42,506, बलरामपुर में 19,605 और श्रावस्ती में 12,056 स्टडी टेबल वितरित की गई हैं। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के नेतृत्व में संचालित इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को घर पर व्यवस्थित और अनुशासित अध्ययन का माहौल उपलब्ध कराना है। 'हर घर बने पढ़ाई का स्थान, हर मेधा को मिले सम्मान' के संकल्प के साथ शुरू की गई यह पहल बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद पत्र से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

सीएनजी गैसकिट लगे वाहन में रिसाव से अफरातफरी

संवाददाता–कुशीनगर। हाटा कोतवाली क्षेत्र स्थित हाईवे पर सुकरौली में सोमवार को सीएनजी गैसकिट लगे वाहन में अचानक रिसाव होने से अफरातफरी का माहौल बन गया। करीब आधे घंटे बाद किसी तरह से रिसाव को बंद किया गया। इस बीच हाईवे पर कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। वाहनों की कतार लगी रही। गोरखपुर से सीएनजी गैसकिट लगा वाहन सोमवार को दोपहर बाद सुकरौली से लेकर हाटा की तरफ जा रहा था। वाहन सुकरौली कस्बे में पहुंचा था कि अचानक सीएनजी गैसकिट वाहन से गैस का रिसाव होने लगा। सीएनजी गैस रिसाव होने का पता चलते ही वाहन चालक ने गाड़ी किनारे की और रिसाव बंद करने के प्रयास में जुट गया। बाजार में मौजूद लोगों ने यह देख अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की कतार लग गई। इस गैस रिसाव से लगभग आधे घंटे तक सुकरौली के लोगों में दहशत का माहौल रहा। चालक दल के सदस्यों ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरह से सीएनजी गैसकिट में रिसाव को बंद करने में सफलता पाई। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और हाईवे पर आवागमन चालू हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिसाव तेज नहीं था। चालक दल ने ही खुद उसे नियंत्रित कर लिया। इस दौरान चालक दल की ओर से वाहन पर पानी की बौछार भी की जाती रहा।

राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर दुकान का निरीक्षण

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। ग्राम पंचायत रेहरा में सोमवार को राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर अधिकारियों ने सरकारी राशन की दुकान का औचक निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई पात्र कार्डधारकों को दो से तीन महीने से राशन नहीं मिला है। वहीं, कोटेदार ने आरोपों को गलत बताते हुए समय पर राशन वितरण करने की बात कही। शिकायतकर्ता राजू यादव, दिनेश यादव समेत अन्य ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें निर्धारित मात्रा में और समय पर राशन नहीं मिल रहा है।

निरीक्षण के दौरान कोटेदार झगरू प्रसाद और शिकायतकर्ता मौजूद रहे। कोटेदार ने कहा कि राशन का वितरण समय पर किया जाता है। उनके मुताबिक, कुछ ग्रामीण राजनीतिक कारणों से शिकायत कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर के एआरओ विजय कुमार ने कोटेदार को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार समय पर पूरा राशन दिया जाए। दुकान के बाहर लाभार्थियों की सूची लगाने और वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी की जा सकती है।

अयोध्या से नहीं तो मेरे खिलाफ जहूराबाद से चुनाव लड़ें, ओपी राजभर की अखिलेश यादव को खुली चुनौती

संवाददाता—अंबेडकरनगर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। सोमवार को न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनौती स्वीकार कर ली है, अब अखिलेश यादव को भी पीछे हटने के बजाय चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबला करना चाहिए। यदि उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ने में कोई परेशानी है तो मेरे सामने जहूराबाद सीट से मैदान में आएं। चुनाव में जनता खुद तय कर देगी कि किसमें कितना दम है। जनपद के प्रभारी मंत्री राजभर ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का बचाव करते हुए कहा कि मृतकों, स्थानांतरित और दूसरे राज्यों में जा चुके लोगों के नाम हटाना जरूरी है। कई लोगों के नाम अलग—अलग स्थानों पर दर्ज होने से मतदाता सूची में गड़बड़ी की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को फार्म भरकर अपने वास्तविक निवास स्थान की जानकारी देनी चाहिए, ताकि उनका नाम सही जगह दर्ज हो सके। मंत्री ने दावा किया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 14 से 16 हजार मृतकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर चुनाव आयोग को निशाना बनाकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने पूर्व के चुनावों में मृतकों के नाम पर मतदान होने का भी आरोप लगाया। राजभर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बजाय विपक्ष को जनता के बीच जाना चाहिए। उन्होने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि ललकार कर भाग जाने वाले को भगोड़ा कहते हैं। उम्मीद है कि अखिलेश भगोड़ा साबित नहीं होंगे। राजभर ने अयोध्या और जहूराबाद का जिक्र करते हुए उन्हें चुनौती दी। राजभर ने कहा कि अखिलेश बड़े—बड़े दावे करने के बजाय जरूरी मुद्दों पर बोलें।

फसल प्रभावित नौ लाख किसानों को 493 करोड़ की मिली राहत, सीएम योगी बोले— नुकसान की भरपाई होगी

संवाददाता—गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं चक्रवात से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान राशि के रूप में डीबीटी के माध्यम से 493 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर जनहानि और पशुहानि भी हुई है। डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 से 10 दिन के अंदर अपने अन्नदाता किसानों को फसल, मकान और पशुधन की क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने 2017 के पहले की सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तब बिजली नहीं आती थी, लेकिन बिल आता था। अब स्थिति बदल गई है। अब अन्नदाता किसान का बिल नहीं आता, बल्कि बिजली आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के 9,18,091 कृषकों के खातों में 493 करोड़ रुपये सीधे भेजे जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इस वर्ष केवल बरसात के दौरान ही अब तक प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि, चक्रवात और बाढ़ से जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह राशि 493 करोड़ रुपये की फसल क्षति सहायता में शामिल नहीं है, बल्कि अलग से दी जा रही है। जिन लोगों के मकान पूरी तरह बह गए या नष्ट हो गए, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तत्काल आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। पशुहानि के मामलों में भी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। कोई जनहानि होती है तो संबंधित परिवार को 24 घंटे के अंदर चार लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर जिन जनपदों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को मिली, वहां किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह राशि सीधे अन्नदाता किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंच रही है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सहायता राशि में कोई बिचौलिया न हो और पैसा सीधे किसान तक पहुंचे। अगर किसान को 25 हजार रुपये

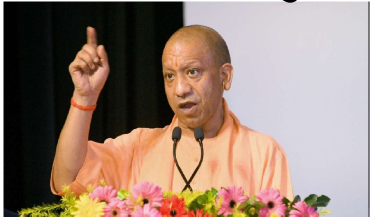

की सहायता स्वीकृत हुई, तो सीधे उसके खाते में पूरे 25 हजार रुपये ही जाएंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय राजीव गांधी ने स्वयं कहा था कि सरकार 100 रुपये भेजती है, लेकिन जमीन पर पहुंचते—पहुंचते केवल 15 रुपये बचते हैं। कांग्रेस व सपा के लोग बीच में ही पैसा खा जाते थे। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा दी जाने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है। बीच में कोई बिचौलिया सेंधमारी नहीं कर सकता। आज 493 करोड़ रुपये अन्नदाता किसानों को मुआवजे के रूप में दिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें संकट की घड़ी में राहत मिल सके। सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है और हर प्रकार का सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में हुदहुद चक्रवात के दौरान फसल को भारी नुकसान हुआ था। भारत सरकार ने उस समय 3,200 करोड़ रुपये भेजे थे, लेकिन किसानों तक केवल 800 करोड़ रुपये ही पहुंच पाए। शेष राशि किसानों तक नहीं पहुंची। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हुदहुद चक्रवात में किसानों को मिली सहायता की स्थिति की जांच कराई तो पता चला कि पूरा पैसा किसानों तक पहुंचा ही नहीं था। इसके बाद अलग से धनराशि की व्यवस्था कर प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध कराई गई। सपा ने किसानों का पैसा खाया, किसानों का श्राप उसको ले डूबा। विपक्ष समाज को जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करता है, लेकिन जनता का पैसा नहीं बांटता।

सीएम ने प्रशासन को निर्देश दिया कि जहां बाढ़ के कारण कटान हुई है और जहां अब भी अतिवृष्टि की शिकायतें आ रही हैं, वहां तत्काल राहत और बचाव कार्य किए जाएं। बाढ़ से बचाव के लिए तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों और बाधित आवागमन को तत्काल चालू किया जाए। इसके लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। आपदा, अतिवृष्टि या चक्रवात के कारण सड़क अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षति होने पर धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सिंचाई विभाग को कटान रोकने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, आवास और विकास प्राधिकरणों को भी क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जैसे ही मौसम साफ हो, तत्काल काम शुरू कराया जाए और आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपदा से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम विकसित करने पर भी काम किया है। पहले आकाशीय बिजली गिरने से बड़ी संख्या में जनहानि होती थी। अब कई जनपदों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो संभावित आकाशीय बिजली की जानकारी पहले ही उपलब्ध कराते हैं। एसएमएस और मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को अलर्ट भेजा जाता है। लोगों को खुले आसमान या पेड़ के नीचे नहीं रहने और पक्के भवन में जाने की सलाह दी जाती है। इससे बड़े पैमाने पर जनहानि रोकने में मदद मिली है। इसके साथ ही रेन गेज लगाए जा रहे हैं, ताकि वर्षा की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके और उसके आधार पर तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। दुर्भाग्य से कोई किसान, बटाईदार अथवा किसान या बटाईदार के परिवार का सदस्य आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आता है, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत संबंधित परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अधिकारियों को इसे तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने बताया कि वर्तमान सहायता राशि से पहले भी बाढ़, चक्रवात और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 169 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 1,29,326 किसानों को फसल क्षति के लिए 78 करोड़ 75 हजार रुपये पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति के मामलों में भी 225 करोड़ 93 लाख रुपये की सहायता पहले वितरित की जा चुकी है। आज कई किसानों को सहायता राशि के डमी चेक प्रदान किए गए हैं, जबकि वास्तविक धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। 2017 से पहले सपा सरकार के समय किसानों को मुआवजा मिलना ही मुश्किल था और यदि मिलता भी था तो दो रुपये, चार रुपये या 15 रुपये जैसी राशि मिलती थी। अब किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है, जिसके एजेंडे में अन्नदाता किसान, युवा, महिलाएं और गरीब हैं। संकट की हर घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अन्नदाता किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने आते ही लघु और सीमांत किसानों की कर्जमाफी के तहत 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। प्रदेश में 16 लाख निजी ट्यूबवेलों की बिजली मुफ्त की गई है। सरकारी ट्यूबवेल से पहले से ही मुफ्त सिंचाई उपलब्ध थी। इसके अलावा नहरों का जाल बिछाया गया है और प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। नए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और सिंचाई की अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

सीएम ने कहा कि जहां बारिश नहीं हुई है, वहां धान खरीद के क्रय केंद्र शुरू हो रहे हैं। जिन जनपदों में अतिवृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर जलभराव हुआ है, वहां 15 अक्टूबर से धान के साथ ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज के क्रय केंद्र शुरू किए जाएंगे। किसानों को अच्छा दाम दिया जाएगा और मंडी तथा क्रय केंद्रों पर किसान अपनी उपज उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार ने खरीद के लिए कोई सीमा तय नहीं की है। किसान जितना धान लेकर आएगा, क्रय केंद्र उसकी खरीद करेंगे। किसानों के लिए कोई टारगेट या रोक—टोक नहीं होगी। जहां अच्छा दाम मिलेगा, किसान वहां अपनी उपज बेच सकता है। यदि कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी और भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर अन्नदाता किसानों का सम्मान किया है। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, फतेह बहादुर सिंह, प्रदीप शुक्ला, डॉ विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह, श्रवण कुमार निषाद और राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चारु चौधरी समेत गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी, पुलिस ने सुरक्षित उतारा

संवाददाता—गोरखपुर। गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी अंतर्गत एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी सोमवार सुबह प्रेमी से शादी करने की जिद में पड़ोसी गांव में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई। खेत की तरफ जा रहे ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सरहरी चौकी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किशोरी को समझाने का प्रयास किया। प्रेमी के आने पर ही नीचे उतरने की जिद करने पर पुलिस ने युवक को मौके पर बुलाया। उसके समझाने के बाद किशोरी टावर से नीचे उतरी। इसके बाद पुलिस दोनों को चौकी ले गई और पूछताछ की। मिली जानकारी के अनुसार, किशोरी की गांव के ही एक युवक से करीब तीन साल से दोस्ती थी। किशोरी युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बात से नाराज होकर वह सोमवार सुबह पड़ोसी गांव मंगलपुर के जगदीशपुर दक्षिणी टोला स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई।किशोरी को टावर पर चढ़ा देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही सरहरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से उसे नीचे उतारने का प्रयास किया। किशोरी ने प्रेमी के आने पर ही नीचे उतरने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने युवक को बुलाया। प्रेमी के समझाने पर किशोरी सुरक्षित नीचे उतर आई। पुलिस दोनों को चौकी ले जाकर मामले में पूछताछ कर रही है।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0— 7942/2026
T202617140207942
धारा 24 उ0प्र0रा0सं0—2006
अदालत— श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय भानपुर बस्ती जिला बस्ती
रामचन्दर
बनाम
अधिशाषी अधिकारी
साकिन जोगिया तप्पा छपिया परगना रसूलपुर, तहसील भानपुर, जिला— बस्ती
1. भुइलोटन पुत्र मनोहर 2. सुमेरे पुत्र मनोहर साकिनान मौजा भानपुर तप्पा छपिया परगना रसूलपुर, तहसील भानपुर, जिला— बस्ती
तारीख पेशी 14—10—2026
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 14 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैस़ला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 10 सन 2029 ई0 जारी किया गया।
— द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0—523/1999
रामकुमार
बनाम
चन्द्रिका
7/1 शिवॉश पुत्र शिवशंकर 7/2 रिंकी 7/3 पिंकी पुत्रीगण शिवशंकर 7/4 गोलू पुत्र शिवशंकर संरक्षक शिवॉश भाई हकीकी साकिन अगई भगाड़ तप्पा पिपरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 25—10—2026
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।
लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 25 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0— 1263/2023
अदालत— श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला बस्ती
ध्रुवचन्द्र तिवारी आदि
बनाम
श्रीमती ऊषा तिवारी आदि
1. श्रीमती ऊषा तिवारी उम्र 52 साल पत्नी सरजू प्रसाद तिवारी साकिन परसाझुगिया तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला बस्ती 2. सरजू प्रसाद तिवारी उम्र 56 साल पुत्र सीताराम साकिन परसाझुगिया तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला बस्ती 3. अमित तिवारी उम्र 25 साल पुत्र सरजू प्रसाद तिवारी साकिन परसाझुगिया तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला बस्ती
—प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
4. रामउजागिर उम्र लगभग 56 साल 5. मंगल प्रसाद उम्र लगभग 61 साल पुत्रगण श्रीनेवास 6. ध्रुवलाल उम्र लगभग 28 साल पुत्र चन्द्रमा प्रसाद 7. सुखदेव उम्र लगभग 50 साल पुत्र मनावर साकिनान मौजा कुतुबपुर तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती
प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
8. कनक भवन वालिग पुत्र मनावर 9. सुखदेव उम्र लगभग 56 साल पुत्र चन्द्रमा प्रसाद साकिनान मौजा कुतुबपुर तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती
प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग
तारीख पेशी 17—12—2026
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 17 माह 12 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैस़ला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
— द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान ग्राम न्यायालय रूधौली बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0—187/2022
हरिश्चन्द्र
बनाम
अजय कुमार आदि
7/1 प्रदीप कुमार उम्र करीब 35 वर्ष 7/2 दिलीप कुमार उम्र करीब 30 वर्ष 7/3 कुलदीप कुमार उम्र करीब 28 वर्ष पुत्रगण हरिश्चन्द्र निवासीगण मौजा करमहिया तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती
तारीख पेशी 21—10—2026
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।
लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 21 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान तृतीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0—259/2021
शशि श्रीवास्तव
बनाम
कुंवर प्रताप सिंह आदि
1. लुल्लुर पुत्र शिवमूरत 2. मायाराम पुत्र शिवमूरत 3. मुकेश पुत्र शिवमूरत साकिनान मौजा मूड़घाट तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 26—11—2026
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।
लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 26 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0— 345/2024
रामभवन आदि
बनाम
श्रीमती प्रमिला आदि
1. श्रीमती प्रमिला पत्नी शिवनाथ उम्र 54 वर्ष साकिन कठिनौली तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती
— विपक्षी प्रथम वर्ग
तारीख पेशी 11—12—2026
हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 11 माह 12 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम माया देवी पत्नी केशपाल यादव ग्राम— हैदराबाद पोस्ट— सिकन्दरपुर जनपद बस्ती (उ.प्र.) की निवासिनी हूं। त्रुटिबश आधारकार्ड में मेरा नाम माया यादव पत्नी केशपाल हो गया है जो गलत है। उसे सुधारकर माया देवी पत्नी केशपाल यादव कराया जाय।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम केशपाल यादव पुत्र मनीराज यादव ग्राम— हैदराबाद पोस्ट— सिकन्दरपुर जनपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी हूं। त्रुटिबश आधारकार्ड में मेरा नाम केशपाल पुत्र मनीराज हो गया है जो गलत है। उसे सुधारकर केशपाल यादव पुत्र मनीराज यादव कराया जाय।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0— 313/2025
शीतला प्रसाद
बनाम
रामलौट आदि
1. रामलौट उम्र 62 साल 2. गंगाराम उम्र 55 साल 3. हीरालाल उम्र 45 साल पुत्रगण राम अवध साकिनान रखिया, तप्पा नवाई, परगना नगर पश्चिम, तहसील हरैया, जिला बस्ती
— विपक्षीगण प्रथम वर्ग
6. राम भवन उम्र 50 साल पुत्र राम लगन निवासी साकिन रखिया, तप्पा नवाई, परगना नगर पश्चिम, तहसील हरैया, जिला बस्ती
— विपक्षीगण द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 02—12—2026
हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 02 माह 12 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0— 126
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0—2006
अदालत— श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बांसी जिला सिद्धार्थनगर
जयराम
बनाम
मोल्हू आदि
साकिन बसठा तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर
1. मोल्हू उम्र 48 वर्ष 2. सोल्हू उम्र 43 वर्ष 3. जोल्हू उम्र 41 वर्ष 4. नतनेश्वर उम्र 22 वर्ष पुत्रगण जयकरन 5. सुशीला उम्र 45 वर्ष 6. उर्मिला उम्र 45 वर्ष पुत्रीगण जयकरन साकिनान मौजा बसठा तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर
—प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
7. ग्राम पंचायत बसठा तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर
—विपक्षी द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 16—10—2026
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैस़ला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
— द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय—
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com